Team of Moody's Investors Service to Reassess India's Rating

4494. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a team of credit rating agency Moody's Investors Service visited New Delhi on June 12, 1998 to discuss and reassess India's Sovereign rating; and

(b) if so, with what results, indicating the factors taken into account in reviewing and revising India's credit?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) As a part of periodic review of Sovereign Rating, M/s. Moody's Investor Service visited India between 10-12 June, 1998. The rating was revised from Baa3 to Ba2. Rating review considers several parameters including macro economy, external sector etc.

Payment of Salary Benefits to the Employees of State Bank of Indore

4495. SHRI K.M. SAIFULLAH:
SHRI GOVINDRAM MIRI:
SHRI YERRA NARAYANASWAMY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether part-payment was made to the employees of Clerical Cadre by the Regional Office, New Delhi of the State Bank of Indore vide their order of October, 1994;

(b) if so, the details of payment made and conditions mentioned therein;

(c) whether the bank has denied payment of salary benefits of past service in reply to Unstarred Question 986 given in the Rajya Sabha on 17th May, 1990;

(d) if so, the reasons for denial of payment initially; and

(e) the action contemplated by Government against the guilty officers and when the remaining payment of salary to the concerned employees are likely to be made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) to (e) Service matters of individual employees of the banks are looked after by the Managements of the banks concerned and employees are free to seek redressal of grievances, if any, before the Competent Authority under the rules. The rules do not envisage any intervention by Government in such matters.

कपूर समिति की सिफारिशें

4496. **श्री रमा शंकर कौशिक:**
श्री रामगोपाल यादव:
श्री राजनाथ सिंह "सूर्य":

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों की आर्थिक और अन्य स्थितियों में सुधार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कपूर समिति की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या है और सरकार द्वारा इन सिफारिशों में से किन-किन सिफारिशों को सही समझा गया है;

(ग) क्या इस मंत्रालय से संबंधित सिफारिशों के संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय द्वारा किन-किन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम्): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार लघु उद्योग के लिए ऋण वितरण प्रणाली के कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 1997 में गठित एस०एल० कपूर समिति ने 30 जून, 1998 को भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत छोटे उद्योगों के साथ विशेष व्यवहार, संमिश्र ऋण की प्रमात्रा में वृद्धि, लघु उद्योग अग्रिमों के रास्ते में आने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाईयों को दूर किया जाना, स्टाम्प शुल्क हटाने और साम्यिक बंधकों की अनुमति देने सहित भूमि को बंधक रखने से संबंधित मामलों को निपटाना, लघु उद्योगों ऋणों का पुनर्वित्त पोषण करने के लिए भारतीय लघु उद्योग